

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग- 1 देहरादून दिनांक जनवरी, 2007
विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003,
संशोधन एवं परामर्श समिति हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3432/नियो०/परा० समिति/2006-07 दिनांक 19.10.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में "उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003, संशोधन एवं परामर्श समिति" हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मु० रू० 4.45 लाख (रूपये चार लाख पैत्तालीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित लेखाशीर्षकों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या-18

2425- सहकारिता आयोजनागत,

800- अन्य व्यय

15- सहकारी समिति संशोधन एवं परामर्श समिति

(धनराशि रू०, हजार में)

मानक मद

सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

04-यात्रा व्यय	50
07-मानदेय	100
08-कार्यालय व्यय	40
13-टेलीफोन पर व्यय	25
15-गाड़ियों का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद	200
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10
42-अन्य व्यय	20

योग-

445

(रूपये चार लाख पैत्तालीस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रश्नगत विषय में जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकर, (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय। जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम०-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(7) उक्त धनराशि का उपयोग विभाग को प्रस्तुत किये गये बिल बाउचर/व्यय प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। तदनुसार व्यय 31 मार्च 2007 तक सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। अवशेष धनराशि 31 मार्च 2007 को अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित की जाय।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425- सहकारिता आयोजनागत-800-अन्य व्यय-15-""उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003, संशोधन एवं परामर्श समिति"" के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला लायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 478/XXVII(4)/वित्त
/दिनांक 5.2.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या १६४ /XIV-1/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. सचिव, मुख्य मन्त्री कार्यालय उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Munir

(ब०आर०टम्टा)

अपर सचिव